

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरौही
बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

प्रार्थी

वीराराम पुत्र चमनारामजी आयु 38 साल
जाति मेघवाल निवासी जावाल
तहसील व जिला सिरौही

बनाम

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 97/2018
अप्रार्थीगण

1-श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नि तगारामजी
आयु व्यस्क जाति मेघवाल निवासी
हाल दक्षिण मेघवालवास सिरौही
तहसील व जिला सिरौही
2-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार
सिरौही

उपस्थित :-

- 1- श्री कलीम अब्बल-वकील प्रार्थी की ओर से
- 2- श्री सुरेशकुमार शाह-वकील अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से
- 3- अप्रार्थी संख्या 2 स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार (तहसीलदार, सिरौही)

राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 राज.कस्त.अधि. 1955 के
वास्ते प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 25 -6-2019



प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान कस्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 1 वास्ते प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा का इस न्यायालय मे दिनांक 20-8-2018 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थी के कदीमी कब्जा व मालकी की मौजा जावाल पटवार हल्का जावाल तहसील व जिला सिरौही मे खसरा संख्या 1964/945 रकबा 0.2800 हैक्टेयर की राजस्व भूमि आई हुई है जिनके पुराने खसरा संख्या 711मी. है। वर्णित राजस्व भूमि पर प्रार्थी का पुराना पुश्तैनी कब्जा है। इस भूमि पर प्रार्थी (Predecessor) बतौर मालिक क काबिज कस्त थे जिन्होने काफी मेहनत मशकत कर इस भूमि को कृषि योग्य बनाया था एवं उनकी मालकी बाबत आज दिन तक इस भूमि पर कोई विवाद किसी भी व्यक्ति नही किया है जिस पर कृषि कार्य कर वे अपना व अपने परिवार का पेट पालते थे। इस भूमि पर प्रार्थी के (Predecessor) कच्चा झोपडा, पशुओं का गोबर तथा अन्य खाद रखने और चारा इकट्ठा करने के लिये बाडा बनाकर तथा कृषि कार्य व मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार सहित निवास करते थे तथा कृषि कार्य करते थे एवं तब से उक्त भूमि पर बाडा इसी कार्य के लिये प्रयोग मे लाया जा रहा है, प्रार्थी के पिता चमनाजी की मृत्यु के बाद से उक्त भूमि पर प्रार्थी का अनवरत बिना किसी रोक टोक के कब्जा है एवं प्रार्थी इस भूमि पर काबिज कस्त है। उक्त भूमि पर हब प्रार्थी द्वारा खेती कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण किया जा रहा है। इस भूमि पर प्रार्थी का पुराना व मालिकाना कब्जा व हक अधिकार करीब 50 सालों से राज्य सरकार एवं अप्रार्थी संख्या 1 की जानकारी मे लगातार शान्तिपूर्ण रहा है। कुछ समय पहले अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के कदीमी कब्जे मालकी की उपरोक्त वर्णित राजस्व आराजी को उसके खातेदारी की बताकर प्रार्थी के विरुद्ध कब्जा हटाने का मुकदमा अर्न्तगत धारा 183 आर.टी.एक्ट के तहत सहायक कलेक्टर महोदय, सिरौही के न्यायालय मे प्रार्थी की जानकारी के बगैर दर्ज करवाकर बारो बार प्रार्थी के विरुद्ध कब्जा हटाने का एक तरफा निर्णय व डिक्री पारित करवायी एवं उसके बाद अप्रार्थी संख्या 1 व उसका पति तगाराम प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि से कब्जा हटाने हेतु दबाव देने लगा, जिस पर प्रार्थी द्वारा उसके पिता के समय से काबिज कब्जा मालकी की भूमि से कब्जा हटाने से स्पष्ट मना करने पर उसने सहायक कलेक्टर महोदय सिरौही से कब्जा हटाने का आदेश उनके पक्ष मे होना बताया तथा कब्जा नही हटाने की अवस्था मे पुलिस कार्यवाही करने की धमकी दी जिस बाबत प्रार्थी द्वारा उसके अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर एक तरफा निर्णय की जानकारी हुई। जिस पर उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील अधिकारी न्यायालय

सहायक कलेक्टर
सिरौही (राज.)

निरन्तर पेश जं. 2

पाली मे अपील प्रस्तुत की गइ जहाँ बाद सुनवाई प्रार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर सहायक कलेक्टर न्यायालय सिरोही को रिमाण्ड किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व उसके पति द्वारा उनकी कारगुारियों सामने आने के डर से प्रार्थी के विरुद्ध वह मुकदमा नोटप्रेस कर खारिज करवाया। अप्रार्थी संख्या 1 का पति तगाराम प्रार्थी का सगा चचेरा भाई है तथा वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के पिता के कदीम से कब्जा कस्त व मालकी की होने तथा चमनाजी व उनके बाद चमनाजी द्वारा उक्त भूमि प्रार्थी को सुपुर्द करने से प्रार्थी के कब्जे कस्त व मालकी की होने की पूर्ण जानकारी अप्रार्थी संख्या 1 श्रीमति शकुन्तला देवी व उसके पति तगाराम को है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 के पति राजस्व कर्मचारी होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी के पिता व प्रार्थी के कब्जे मालकी की उपरोक्त भूमि मे अप्रार्थी संख्या 1 का नाम दर्ज करवा दिया जो कि गलत है। जबकि उपरोक्त राजस्व भूमि के वास्तविक मालिक प्रार्थी के पिता चमनारामजी थे। प्रार्थी के पिता द्वारा भी उपरोक्त भूमि पारिवारिक सेटलमेण्ट मे प्रार्थी को दी थी जिसमे प्रार्थी के भाई अशाराम द्वारा पूर्ण सहमति दी थी। उक्त भूमि पर पुराना पुश्तैनी कब्जा कस्त व बाडा एवं प्रार्थी का काफी पुराना कब्जा है इस भूमि पर प्रार्थी का बहुत पुराना व प्छातवर्ती कब्जा राज्य सरकार व अप्रार्थी संख्या 1 व उसके परिवार की जानकारी मे शान्तिपूर्ण रहा है जिससे भी इस भूमि को नियमन कराने अथवा खातेदारी प्राप्त करने के हक व अधिकार प्रार्थी को ही प्राप्त हो चुके है जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का पेश करने का कारण पैदा हुआ है। प्रथम दृष्टियों मामला प्रार्थी के पक्ष मे है प्रार्थी अपने पिता के समय से कदीम से वादग्रस्त आराजी पर बतौर मालिक काबिज है, केवल अप्रार्थी संख्या 1 के पति प्रार्थी के चचेरे भाई होने से उस पर भरोसा करने पर उसके द्वारा धोखे से प्रार्थी के पिता चमनाराम के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करवा देने से अप्रार्थी संख्या 1 को वादग्रस्त संपत्ति मे कोई हक अधिकार पैदा नही होते है तथा न ही उससे वादग्रस्त आराजी मे प्रार्थी के हक अधिकार किसी तरह से प्रभावित होते है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी मे करीब 50 सालों से ही मालिक व काबिज है, जिससे प्रार्थनापत्र संख्या 2 पैरा मे वर्णित राजस्व आराजी मे प्रार्थी के कब्जे मालकी व हक हिस्से की राजस्व आराजी से प्रार्थी को कृषि करने से रोकने, एवं उस पर जबरन अवैध रूप से कब्जा करने का अथवा राजस्व रेकर्ड मे नाम होने का नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमि को उपयोग उपभोग करने का अप्रार्थी संख्या 1 या अन्य किसी भी व्यक्ति को कोई हक व अधिकार नही है। यदि अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित नही किया गया तो वे जबरन कमजोर प्रार्थी के कब्जे मे हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे तथा अप्रार्थी प्रार्थी के कमजोर व अकेले होने का फायदा उठाकर प्रार्थी के कब्जे मालकी की उपरोक्त आराजी पर जबरन अवैध रूप से कब्जा कर सकते है तथा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड मे अप्रार्थी संख्या 1 का नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर उसे बारो बार बेचान या खुर्द बुर्द कर देंगे जिससे प्रार्थी का प्रस्तुत वाद का मकसद ही समाप्त हो जायेगा तथा वाद बाहुल्यता की प्रवृत्ति बढेगी एवं प्रार्थी को अतुलनीय व अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थी के पक्ष मे एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस अश्व्य का अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश जारी करना फरमावे कि ताफैसला वाद अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त वर्णित राजस्व आराजी अथवा उसके किसी भी हिस्से पर प्रार्थी की सहमति बगैर प्रवेश करने, उसमे विधिविरुद्ध रूप से जबरन कब्जा करने की कोशिश करने, से अप्रार्थी संख्या 1 को रोका जाने तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वयं, उसके पति, स्तिेदार, ठेकेदार मजदूर अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति के जरिये वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थी के शान्तिपूर्ण कब्जे व उपयोग व उपभोग मे किसी प्रकार से कोई भी बाधा अथवा अवरोध कारित करने से रोका जाने तथा वादग्रस्त आराजी मे अप्रार्थी संख्या 1 का नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी को बारो बार बेचान, रहन, दान अथवा किसी भी प्रकार से व्ययन करने से रोके जाने के अश्व्य का अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश जारी करना फरमावे।

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

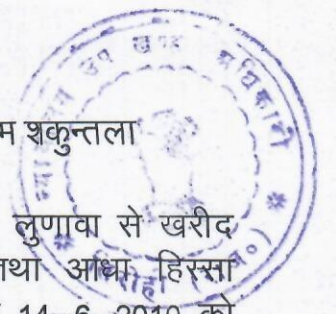
शिरुत ए पेज नं. 3

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 में वर्णित दस्तावेजात सूची अनुसार पटवारी हल्का जावाल का प्रमाण पत्र दि 13-11-17 विगोटी रसीद क्रमांक 62439-62291 जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 खाता नंबर नया 741 खसरा नंबर 1964/945 रकबा 0.2800 हैक्टेयर नक्शा किस्तवार मिलान क्षेत्रफल वादपत्र अर्न्तगत धारा 183 आरटीएक्ट, माननीय अपील प्राधिकारी कोर्ट पाली का निर्णय दिनांक 23-6-2016 राजस्व वाद संख्या 12/2014 के आदेशिका दि 24-1-2014 से लगातार दि 13-11-2017 की प्रतियाँ मौके के फोटोग्राफस प्रतियाँ का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टियों सहमत होने से उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 20-8-2018 को न्यायालय में दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये जिस पर उक्त नोटिस बाद तामिल इस न्यायालय में प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया ।

विचारण प्रकरण में इस न्यायालय में सुनवाई पेशी दिनांक 16-1-2019 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 7-1-2019 को शामिल मिसल किया गया तथा जवाब की प्रति वकील प्रार्थी को दिलवाई गई । अप्रार्थी संख्या एक ने अपने जवाब में पैरा संख्या 2 के कथन की हकीकत को सत्य होने से स्वीकार किया गया । प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 के उत्तर में निवेदन किया कि इस पद की सम्पूर्ण हकीकत असत्य होने से अप्रार्थीयों अस्वीकार करती है । वादग्रस्त कृषि भूमि पर न तो प्रार्थी का न ही उनके पिताजी व भाई अशाराम तथा पूर्वजो का कोई कब्जा कस्त ही रहा है न ही वादग्रस्त कृषि भूमि पर कोई वाडा ही बना हुआ है और नही प्रार्थी व उससे पूर्वज का बिज कस्त होने का कथन असत्य होने से अस्वीकार है वरन मौके पर कब्जा अप्रार्थीया श्रीमती शकुन्तलादेवी का है और तारबंदी की हुई है तथा मौके पर कोई फसल नही बोई हुई है । प्रार्थनापत्र के पद संख्या 4 के उतर में निवेदन किया कि इस पद की सम्पूर्ण हकीकत असत्य होने से अस्वीकार है । प्रार्थी का बहुत पुराना व मालकाना कब्जा व हक अधिकार करीब 50 सालों से राज्य सरकार व अप्रार्थीगण संख्या 1 की जानकारी में लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा कस्त होने का कथन असत्य होने से अस्वीकार है । अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के पिता चमनाजी व उसके भाई अशाराम द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी व कब्जे कस्त की कृषि भूमि में अवैध रूप से अतिक्रमण किये जाने पर धारा 183 आर.टी.एक्ट के तहत चमनाजी व अशाराम के विरुद्ध दावा अक्षय प्रस्तुत किया था जिसके निर्णय व डिक्री अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में हुआ था और उससे पश्चात प्रार्थी के पिता चमनाजी व अशाराम ने राजस्व अपीललेण्ट कोर्ट केम्प पाली में अपील अक्षय प्रस्तुत की थी जो रिमाण्ड हेतु पुनः सुनवायी हेतु श्रीमान के न्यायालय में मुकदमा लौटाया गया था और प्रार्थी के भाई अशाराम द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि का कब्जा दिनांक 11-2-2017 को राजीनामा मौके पर कब्जा अप्रार्थी संख्या 1 को सुपुर्द किया था तब से लगाकर आज दिन तक कब्जा मौके पर अप्रार्थीगण संख्या 1 का है । उक्त राजीनामा फौजदारी केस अर्न्तगत धारा 447/34 आई.पी.सी. में फौजदारी प्रकरण संख्या 487/2011 में पफौजदारी प्रकरण जरिये राजीनामा लोक अदालत दिनांक 15-2-17 को फैसल की गई थी और उक्त फौजदारी मुकदमे के दौरान प्रार्थी के पिता चमनाजी का स्वर्गवास हो जाने से राजीनामा अशाराम द्वारा किया गया था । वास्ते सबत उक्त फैसले व राजीनामा की नकले साथ में प्रस्तुत है । प्रार्थनापत्र के पद संख्या 5 व 6 के उतर में निवेदन है कि पदों की सम्पूर्ण हकीकत असत्य होने से अस्वीकार करते हैं । तगाराम अप्रार्थी संख्या 1 का पति अक्षय है परन्तु उन्होंने पटवारी पद पर कोई दुरुप्योग आज दिन तक नही किया है एवं प्रार्थी ने जानबुझकर लोगो की सिखावट में आकर मनगढन्त तथा उपरोक्त पैरा में लिखवाये हैं जो अप्रार्थीगण अस्वीकार करते हैं । अप्रार्थी संख्या 1 के पति तगाराम ने स्वर्गीय चमनारामजी ने किसी से कोई रकम प्राप्त नही की है और न ही राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी अथवा उनके भाई या उनके पिता के नाम अथवा अन्य किसी के नाम खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने की कोई बात ही कही है । शेष प्रार्थनापत्र के पद संख्या 7 से 12 तक का कथन अस्वीकार कर निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा कस्त है । अप्रार्थी संख्या 1 ने उपरोक्त कृषि भूमि में से आधा हिस्सा

सहायक कलेक्टर
खिरोड़ी (राज.)

अशाराम
द्विस्त एपेज नं. 4



दिनांक 23-6-2010 को नरींगाराम पुत्र पनाजी जाति मेगवाल निवासी लुणावा से खरीद कर उसकी रजिस्टरी करवायी थी तथा कब्जा प्राप्त किया था तथा आधा हिस्सा फुलाराम पुत्र तेजारामजी मेगवाल पालडीजोड से मोल किमतन दिनांक 14-6-2010 को खरीद कर रजिस्टरी करवायी थी एवं आधा हिस्सा का कब्जा इनके प्राप्त किया था। इस प्रकार उपरोक्त वादग्रस्त खसरा नंबर की सम्पूर्ण रकबा यानि खसरा संख्या 1964/945 रकबा 0.12700 हेक्टेयर कृषि भूमि खरीद कर पूर्ण रकबा का कब्जा प्राप्त किया था तथा मुटेशन भी अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में हो चुका है तथा आज दिन तक कब्जा व अस्त अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा है। प्रार्थी का उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर न तो कभी कब्जा रहा है और न ही उनके पिताजी चमनाराम व उसके भाई अन्नाराम अथवा उनके पूर्वजों का कोई कब्जा ही रहा है। जिससे एडवर्स पजेशन की स्टोरी गलत होने से व असत्य होने से अप्रार्थी संख्या 1 स्वीकार करती है तथा प्रार्थी का कोई प्राथम दृष्टियों केस प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि अप्रार्थीया ने वादग्रस्त कृषि भूमि जरिये बेचान लिखत से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था तथा उसका मुटेशन भी अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में हो जाने से अप्रार्थी संख्या 1 उपरोक्त वादग्रस्त खसरा संख्या 1964/945 रकबा 0.2800 हेक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार कृषक है एवं मौके पर तारबंदी की हुई है कोई फसल नहीं बोई है तथा जे.सी.बी. से भूमि को समतल करायी है जो आज भी मौके पर मौजूद है जबकि प्रार्थी ने तत्कालीन पटवारी से मेल मिलाप कर कब्जे का सर्टीफिकेट प्राप्त किया है जो विधि विरुद्ध है। इस प्रकार प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टियों केस नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त कृषि भूमि का खातेदार कृषक है एवं प्रार्थी के पिता स्वर्गीय चमनारामजी द्वारा व उसके भाई अन्नाराम द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किये जाने पर फौजदारी प्रकरण में आपसी राजीनामा के जरिये अन्नाराम ने मौके पर कब्जा पुनः अप्रार्थीगण संख्या 1 को सुपुर्द कर दिया था। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 उपरोक्त कृषि भूमि की खातेदार कृषक है एवं काबिज कस्त है जिससे अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्रार्थी के पक्ष में पारित हो जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 को अतुलनीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयो पैसो में आका नहीं जा सकता है और बहु विवाद में उलझना पड़ेगा और सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण संख्या 1 के पक्ष में है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 का निवेदन है कि प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट बाबत प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा का खारीज करवाना फरमावे।

विचारण प्रकरण में सुनवाई पेन्नि दिनांक 16-1-2019 को दौराने सुनवाई अप्रार्थी संख्या 2 स्टेट की ओर पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि प्रकरण में स्टेट तहसीलदार, सिरोही फोरमल पक्षकार होने तथा राजहित प्रभावित नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 2 स्टेट का जवाब देने की आवश्यकता नहीं होने ससे जवाब बंद करावे जिस पर न्यायालय द्वारा पैरोकार सरकार के निवेदन पर अप्रार्थी संख्या 2 का जवाब बंद किया गया।

इस न्यायालय में विचारण प्रकरण में वास्ते प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर वकील प्रार्थी तथा वकील अप्रार्थी संख्या 1 की अंतिम बहस दिनांक 3-6-2019 को रखी गई। जिस पर वकील प्रार्थी तथा वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने सुनवाई न्यायालय में हाजिर होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई।

हमने विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय प्रार्थनापत्र अ.धा. 212 आर.टी. एक्ट व जवाब तथा संलग्न उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड की प्रतियों का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन व क्लिफेण के उपरान्त यह पाया गया कि अप्रार्थीयों जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 खाता संख्या 241 मौजा जावाल के वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 1964/945 रकबा 0.2800 हेक्टेयर की खातेदार कृषक है। प्रार्थी के भाई अन्नाराम द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि का कब्जा दिनांक 11-2-2017 को राजीनामा मौके पर कब्जा अप्रार्थी संख्या 1 को सुपुर्द किया था तब से लगाकर आज दिन तक मौके पर कब्जा अप्रार्थीया का है। उक्त राजीनामा फौजदारी प्रकरण संख्या 487/2011 में जरिये राजीनामा लोक अदालत में दिनांक 15-2-2017 को फैसल हुई है। इस प्रकार विचारण प्रकरण में अप्रार्थीया

वादग्रस्त कृषि भूमि की खातेदार कृषक होने से प्रथम दृष्टियों मामला अप्रार्थीया के पक्ष में जाना जाहिर होता है तथा खातेदार के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी करने से सुविधा का संतुलन विपरित रूप से हितो को प्रभावित कर सकता है तथा अप्रार्थीया को बिना किसी वजह के वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा करने से रोकना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। यह निर्विवाद है कि विवादित भूमि अप्रार्थीयों के नाम पर खातेदारी हक के दर्ज है प्रार्थीगण इस भूमि पर प्रतिकूल आधिपत्य (एडवर्स पजेशन) के आधार पर अपने पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहते हैं। राजस्थान कब्जाकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के मामले में सम्बन्धित पक्षकार को अपने पक्ष में प्रथम दृष्टियों प्रकरण जो प्रथम दृष्टियों टाइटल एवं प्रथम दृष्टियों आधिपत्य पर आधारित हो, प्रमाणित करना होता है। परन्तु विवेचनाधीन प्रकरण में प्रार्थीगण के पक्ष में न तो प्रथम दृष्टियों टाइटल है तथा न ही प्रथम दृष्टियों आधिपत्य ही प्रमाणित है। कानूनी नजीर आर.आर.डी. 2011 पेज 563 -564 सोनीदेवी वगैहरा बनाम मीठूलाल वगैरहा में यह प्रतिपादित किया है कि अभिलिखित खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थीगण अपने पक्ष में प्रथम दृष्टियों मामला टाइटल व प्रथम दृष्टियों मामला आधिपत्य हेतु सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति सिद्ध करने में असफल होने के फलस्वरूप प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीयों बाबत प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार(खारिज) किया जाता है। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही (राज.)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 25-6-2019 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया।



सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही (राज.)